

IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, PURNEA.**Mutation Revision No.- 99/2022**

Prabha Devi & Anr Petitioners.

Versus

The State of Bihar & Ors Opposite Parties.

Serial No.	Date of order of proceeding.	Order with signature of the court.	Office action taken with date
1	2	3	4
	19.10.2023	<p style="text-align: center;"><u>आदेश</u></p> <p>प्रस्तुत Mutation Revision न्यायालय, अपर समाहर्ता, किशनगंज द्वारा लगान निर्धारण अपील वाद सं०-08/2018-19 में दिनांक-15.03.2022 को पारित आदेश के विरुद्ध दायर किया गया है। विलंब क्षांत हेतु पृथक आवेदन दाखिल है।</p> <p>उभय पक्षों को वाद के पोषणीय बिंदु पर सुना गया। आवेदिका की ओर से प्रस्तुत वाद बिहार भूमि दाखिल-खारिज अधिनियम 2011 की धारा 7 (a) सह पठित Bihar Board's Miscellaneous Rules 1958 की धारा 3 के अंतर्गत दायर किया गया है।</p> <p>अभिलेख में संलग्न दस्तावेजों के अवलोकन से विदित होता है कि आवेदिका द्वारा अपर समाहर्ता, किशनगंज द्वारा भू-लगान निर्धारण में पारित आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत वाद दायर किया गया है। उक्त आदेश के अंतिम पूर्व कंडिका में नगरपालिका सर्वे खाता सं०-175, खेसरा सं०-756 की आधे-आधे हिस्से की भूमि की जमाबंदी पक्षकारों के बीच कायम करने/संशोधित करने का आदेश दिये जाने में प्रक्रियात्मक त्रुटि परिलक्षित होती है। चूँकि लगान निर्धारण मामले में मात्र लगान निर्धारण संबंधी आदेश पारित किये जाने के पश्चात् प्रक्रियात्मक तरीके से अंचलाधिकारी के समक्ष नामांतरण के माध्यम से जमाबंदी सृजित किये जाने की परिपाटी है। इस प्रकार भू-लगान निर्धारण मामले में अपर समाहर्ता द्वारा जमाबंदी कायम करने का आदेश विधिसम्मत नहीं माना जा सकता है।</p> <p>बिहार भूमि दाखिल-खारिज अधिनियम 2011 अध्याय VII "जमाबंदी का रद्दीकरण" (Cancellation of Jamabandi) की धारा 9 की उपधारा 7 (a) स्पष्टतः जमाबंदी रद्दीकरण से संबंधित है जो प्रस्तुत वाद में पोषणीय नहीं है। जबकि विपक्षी सं०-03 से 08 के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि बिहार भूमि दाखिल-खारिज अधिनियम अथवा Bihar Board's Miscellaneous Rules 1958 के अंतर्गत भू-लगान निर्धारण का कोई प्रावधान नहीं है बल्कि भू-लगान निर्धारण की कार्यवाही B.T. Act 1885 की धारा 158 (C) के अंतर्गत भूमि सुधार</p>	

लगातार
19.10.2023

उप समाहर्ता/अनुमंडल पदाधिकारी को मूल क्षेत्राधिकार प्राप्त है। इनके आदेश के विरुद्ध उक्त धारा के अंतर्गत समाहर्ता/अपर समाहर्ता के समक्ष अपील का क्रमशः

प्रावधान निरूपित है। समाहर्ता/अपर समाहर्ता के आदेश के विरुद्ध द्वितीय अपील अथवा पुनरीक्षण का कोई प्रावधान नहीं है। आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता द्वारा इसका कोई खंडन नहीं किया गया। विद्वान सरकारी अधिवक्ता द्वारा भी इस तथ्य पर सहमति जतायी गई।

अतः उपर्युक्त के आलोक में प्रस्तुत वाद के गुण-दोष (Merit) पर बिना विचार किये इसे इस न्यायालय में "पोषणीय नहीं" (Not Maintainable) पाते हुए अस्वीकृत किया जाता है। इसी के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। आदेश की प्रति के साथ निम्न न्यायालय मूल अभिलेख वापस भेजें।
लेखापित एवं शुद्धित।

आयुक्त,
पूर्णिमा प्रमंडल, पूर्णिमा।

आयुक्त,
पूर्णिमा प्रमंडल, पूर्णिमा।

--	--	--	--

Web Copy. Not Official.